

# बार-बार ब्याज दर घटाने के बाद भी बाज़ार में डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है

‘जेब में पैसा होना ही पर्याप्त नहीं है, खरीददारी करने के लिए उपभोक्ता में इच्छा होना भी जरूरी है’

—सुकुमार साह—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 5 अगस्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा व्याज दरों में लगातार कटौतियों के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि सस्ता ऋण धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेगा, लेकिन इसके बावजूद समग्र आर्थिक परिदृश्य और अधिक धुंधला होता जा रहा है, जबकि महंगाई में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे आरबीआई को कुछ हद तक निर्णय लेने की गुंजाइश मिली है, फिर भी अपेक्षित आर्थिक वृद्धि सामने नहीं आई है। मॉनेटरी ईजिंग और वास्तविक आर्थिक परिणामों के बीच यह असम्बद्धता सवाल खड़े कर रही है कि क्या आरबीआई अब अपनी हद तक पहुंच चुकी है, जहाँ वह अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकती।

भारत की खुदरा महंगाई दर घटकर छह साल के निचले स्तर लगभग 2.1 – 2.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जिसका प्रमुख कारण कमजोर मांग और कोर मूल्यों में गिरावट है। लेकिन यह ज़रन मनाने का कारण नहीं है। वे क्षेत्र, जो उपभोक्ता भावनाओं पर सबसे अधिक

■ रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, ब्याज दर में कटौती कोई “जादू की छड़ी” नहीं है, अगर बाज़ार की दशा सुधारनी है तो इन्फ़ास्ट्रक्चर से लेकर स्किल तक हर स्तर पर गहन सुधार करने होंगे।

■ खुदरा बाज़ार में महंगाई 6 साल में सबसे कम स्तर पर है, पर, यह खुशी की बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार ठप्प है, खासकर रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी मंदी है। इस वर्ष जून में कारों की बिक्री 18 माह में न्यूनतम स्तर पर रही है, बड़े शहरों में जमीनों की खरीद फरोख्त में भारी कमी आई है।

■ इसका संकेत साफ है, माँग कमजोर है और इतनी कमजोर है कि सिर्फ़ ब्याज दर में कटौती से कुछ नहीं होगा।

निर्भर करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। जून में कार बिक्री 18 महीनों के निचले स्तर पर आ गई और वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में प्रमुख शहरों में संपत्ति लेन-देन में भारी गिरावट दर्ज की गई। संदेश साफ है: मांग कमजोर है, और केवल दरों में कटौती से इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

चिंता की एक और बात यह है कि पॉलिसी दरों में गिरावट के बावजूद, व्यावसायिक बैंक ऋण देने में हिचक रहे हैं। खुदरा ऋण वृद्धि में भारी गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड और वाहन ऋण जैसे क्षेत्रों में, जहां बकाया राशि तेजी से बढ़ रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेडिट कार्ड पर 90 दिनों की बकाया राशि जून 2025

तक साल-दर-साल दोगुनी होकर 338 अरब हो गई है। जोखिम बढ़ने के चलते बैंक अपने मानदंडों को सख्त बना रहे हैं, जिससे सस्ता फंड भी लोगों और व्यवसायों तक नहीं पहुंच पा रहा। जहाँ दरों में कटौती लागू भी की गई है, वहाँ भी आम उपभोक्ताओं और व्यवसायों तक इसका असर पहुंचने में समय लग रहा है। फरवरी से आरबीआई ने रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइन्ट की और कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) में भी 100 बेसिस पाइन्ट्स की कटौती की है, लेकिन बैंकों के माध्यम से इसका प्रभाव आंशिक ही रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि व्याज दरों में कटौती संरचनात्मक बाधाओं—जैसे धीमी अवसंरचना प्रगति, जटिल विनियमन और कमजोर सरकारी खर्च को दूर नहीं कर सकती, जो व्यावसायिक विश्वास पर असर डालते हैं।

बाहरी चुनौतियाँ भी इस स्थिति को और बिगाड़ रही हैं। वैश्विक मांग कमजोर है, और अमेरिका द्वारा लगाए गए नए शुल्क जैसे भू-राजनीतिक दबावों ने भारत के निर्यात को प्रभावित किया है। इसके साथ ही, भारत की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कावड़ यात्रा में भगदड़ से दो महिलाओं की मौत

सीहोर, 05 अगस्ता मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार को अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें जहाँ घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं की हालत काफी गंभीर है। बता दें, कुबेरेश्वर धाम को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए जाना जाता

■ कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा में भक्तों की अत्यधिक भीड़ उमड़ी और भगदड़ मच गई।

है। दरअसल, 6 अगस्त को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की अगुवाई में कांवड़ यात्रा निकाली जानी है। यात्रा से पहले सीवना नदी घाट से कुबेश्वर धाम तक भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात ये हैं कि इंदौर-भोपाल हाइवे पर जाम की स्थिति बन गई है। इसी बीच कुबेरेश्वर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन

नयी दिल्ली, 05 अगस्ता बिहार और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और मशहूर किसान नेता सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे।

सोशल मीडिया एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार, उन्हें गत 11 मई

■ गत 11 मई से वे संक्रमण की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती थे।

को अस्पताल में संक्रमण को शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। किडनी की समस्या के कारण उनकी अस्पताल में डायलिसिस की जाती थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुःखी हूँ। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति।”

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा कि लोग उन्हें हमेशा ऐसे इंसान के रूप में याद रखेंगे, जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा आप प्रमुख अरविन्द्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# भारत को धमकाने वाले ट्रंप चीन पर चुप हैं, चीन ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है

चीन ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री भी मानते हैं, ट्रंप धमकी देते हैं और हमेशा पीछे हट जाते हैं (ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट)

—अंजन रॉय—  
—अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि—  
वॉशिंगटन, 5 अगस्ता जब भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना जारी रखा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उस पर जोरदार हमला बोला। लेकिन चीन द्वारा इससे भी अधिक मात्रा में रूसी तेल आयात करने पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा है।

ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने भी उस भाषा का प्रयोग किया जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बेहतर समझते हैं, “दादागिरी”। ट्रंप की प्रतिक्रियाएँ, ट्रंप को लेकर वॉल स्ट्रीट और चीन की परिभाषा को सही साबित करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी उस छवि पर खरे उतरे हैं जिसे “टाको”

■ ट्रंप ने चीन को भी टैरिफ वृद्धि की धमकी दी, पर, जैसे ही चीन ने “रेअर अर्थ मेनेट” की आपूर्ति रोकने की धमकी दी, ट्रंप ने चीन का उल्लेख करना ही छोड़ दिया।

■ यही नहीं, वे यूरोप के देशों पर भी मौन ही रहते हैं, जो गैस आपूर्ति के लिए पूरी तरह से रूस पर आश्रित हैं। खुद अमेरिका भी रूस से काफी आयात करता है।

## ‘भारत पर 24 घंटे में और टैरिफ बढ़ाऊंगा’

नई दिल्ली, 05 अगस्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी देते हुए कहा कि वह टैरिफ में भारी वृद्धि करेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा, “भारत, रूस से सामान खरीद रहा है।

■ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को एक और धमकी दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

(टी.एस.सी.ए.) कहा जाता है, अर्थात् “ट्रंप ऑलवेज़ चिकन्स आउट” (ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं)।

जब ट्रंप ने चीन पर अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो चीन ने जवाब में अमेरिका को दुर्लभ खनिजों और मैनेट्स की आपूर्ति रोकने की धमकी दी। जब ट्रंप को इन खतरों का असर समझ आया, तो वे तुरंत पीछे हट गए और चीनी सामानों पर टैरिफ कम कर दिया। भारत के मामले में ट्रंप ने ज्यादा टकराव का रुख अपनाया। एक अमेरिकी समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात तुरंत नहीं रोकता, तो वे भारतीय निर्यात पर एक दिन के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## खड़गे -राहुल- प्रियंका ने धराली के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की

नयी दिल्ली, 05 अगस्ता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में

■ उन्होंने सरकार से बचाव कार्यों में और तेजी लाने की अपा

आज बादल फटने की घटना पर गहरा दुःख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। खरगे ने सोशल मीडिए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “उत्तराखंड के धराली (उत्तरकाशी) में बादल फटने से हुई तबाही वाकई दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा, “इस भयानक त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। लापता लोगों के सुरक्षित लौटने की कामना करता हूँ। कांग्रेस के साथियों से अपील है कि वे राहत और बचाव कार्य में हरसंभव मदद करें। राहुल गांधी ने कहा धराली में बादल फटने से आई भारी तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुःख (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## उत्तराखंड में पीड़ितों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी - मोदी

नयी दिल्ली, 05 अगस्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों के कुशलक्षेम की कामना भी की है।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की और स्थिति का जायजा लिया। मोदी

■ अमित शाह ने आईटीबीपी की तीन टीम तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार टीम घटनास्थल पर भेजीं।

ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूँ। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शाह ने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली है। आईटीबीपी की निकटतम तीन टीमों को वहाँ भेज दिया गया है, साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार टीमों भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुँच कर बचाव कार्य में मदद करेंगे।

# उत्तरकाशी में बादल फटा, मात्र 34 सैंकेड में सैकड़ों घर और होटल मलबे में बदले

सेना के 8-10 जवान सहित, अभी तक 50 से ज्यादा लोग लापता

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 5 अगस्ता उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार, 5 अगस्त को इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बादल फटने की घटना हुई, जिसने भारी तबाही मचाई। यह हादसा गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले मार्ग के एक प्रमुख पड़ाव धराली में हुआ, जिससे खीर गंगा नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में लगभग 20 से 25 होटल और होमस्टे पूरी तरह तबाह हो गए। हर्षिल क्षेत्र में सेना के एक बेस को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान के समाचार मिले हैं। बहुत से होटल और मकान मलबे में दब गए हैं और कई लोगों के लापता होने की आशंका है। हालांकि अभी तक मृतकों और लापता लोगों की आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन अप्रुष्ट खबरों के मुताबिक करीब 4 लोगों की मौत हुई



उत्तराखंड के धराली गांव में हुए भूस्खलन के वीडियो से दो फोटोएं निकाली गई हैं, जो इस भूस्खलन से हुए भारी विध्वंस को दर्शाती हैं।

है और बड़ी संख्या में होटल कर्मों व मजदूर लापता हैं। स्थानीय लोगों द्वारा साझा किए गए वीडियोज़ में देखा जा



सकता है कि धराली के कई होटल और मकान तिनकों की तरह बह गए। एक स्थानीय निवासी ने प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर बताया कि हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने के बाद आई तेज बाढ़ में शहर के कम से कम 20 निवासी बह गए।

अधिकारियों का कहना है कि जान-माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इस आपदा की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके के लिए रवाना कर दिए गए हैं।

■ मंगलवार दोपहर 2 बजे धराली में बादल फटा, जो कि गंगोत्री जाने के रास्ते का प्रमुख पड़ाव है। बादल फटते ही खीर गंगा नदी तुरंत उफान पर आ गई और उसके बहाव में सैकड़ों घर, होटल आदि बह गए।

■ प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, इसमें वायु सेना की भी मदद ली गई है।

■ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर गहरा दुःख जताया।

मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे धराली कस्बे के पास बादल फटा, जिससे खीर गंगा में अचानक बाढ़ आ गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह दिल दहला देने वाली बाढ़ पल भर में सब कुछ बहा ले गई।

बाढ़ को देखकर, कई ग्रामीणों ने शोर मचाकर और सीटी बजाकर लोगों को सतर्क किया। वहाँ, आपातकालीन कार्यवाही केन्द्र (इमर्जेंसी ऑपरेशंस सेन्टर) से मिली जानकारी के अनुसार, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शोर मचाकर और सीटी बजाकर लोगों को सतर्क किया। वहाँ, आपातकालीन कार्यवाही केन्द्र (इमर्जेंसी ऑपरेशंस सेन्टर) से मिली जानकारी के अनुसार, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## विचार बिन्दु

अगर तुम गलतियों को रोकोगे, तो भी सत्य बाहर आ जायेगा। –टैगोर

# भारतीय अर्थव्यवस्था परवान चढ़ती हुई या मरी हुई!

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक विवादस्पद टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि “भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है”। विपक्ष के नेता ने मरी हुई अर्थव्यवस्था का शब्द अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान से लिया था जिसमें भारत और रूस के बीच चरित्र संबंधों को लेकर तीखा हमला बोला गया था और कहा गया था कि भारत और रूस दोनों देश मिलकर अपनी “मृत अर्थव्यवस्थाओं” को गत में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी का ट्रम्प की टिप्पणी को समर्थन करता यह कथन न केवल राजनीतिक दृष्टि से तीखा था, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अनेक बहसों को जन्म देने वाला साबित हुआ। यहां यह सवाल भी स्वाभाविक रूप से उठा कि क्या विपक्ष के नेता का यह बयान एक राजनीतिक अतिशयोक्ति है या इसके पीछे ठोस तथ्य और आंकड़े भी मौजूद हैं? बेहतर होता विपक्ष के नेता अपने कथन को साबित करने वाले तथ्य भी साथ में देते। मीडियाकर्मियों ने भी उनसे उसी प्रकार कोई उलट सवाल नहीं किया जिस प्रकार के सवाल नहीं करने के आरोप प्रधानमंत्री समर्थक मीडिया पर उठते आए हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि आम जनता की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी अक्सर सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रश्न उठाते रहे हैं, लेकिन उनका देश की अर्थव्यवस्था को “मरी हुई अर्थव्यवस्था” कहना एक गंभीर आरोप है, जिसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था न केवल संकट में है बल्कि उसमें सुधार की गुंजाइश भी नागण्य है। राजनीतिक दृष्टि से यह बयान उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें एक ऐसा प्रहार है जो जनता को सोचने पर मजबूर करे कि ‘अमृतकाल’ और ‘5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ की बातें ज़मीनी हकीकत से कितनी मेल खाती हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दो प्रकार की अपेक्षित प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक वर्ग ने उन्हें ‘नकारात्मक मानसिकता’ वाला कहा, तो दूसरे ने कहा कि “कम से कम कोई तो ज़मीन की बात कर रहा है।” लेकिन यह भी दिलचस्प है कि राहुल गांधी की पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेताओं शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने बयान दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

सरकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत एक मजबूत और संभावनाओं से भरी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भी स्थिरता बनाए हुए है। सरकार के समर्थकों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था “मृत अर्थव्यवस्था” होने से कोसों दूर है। वास्तव में, यह अपनी गतिशील और अपनी विविधता वाली संरचना के साथ, विश्व स्तर पर सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वे मजबूत विकास दर के आकड़ों का हवाला देते हैं। जैसे वित्त वर्ष 23/24 में भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे यह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। इसका श्रेय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रियल एस्टेट में घरेलू निवेश तथा साथ में 9.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र को दिया जाता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसके 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है। भारत वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ी और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 में 3.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसके 2025 में इसके जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है और 2027-2030 तक इसके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।

आर्थिक विकास को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्र में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है जो सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत का योगदान देता है। इसमें आईटी, वित्त और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमुख है। भारत के आईटी-बीपीएम क्षेत्र का 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है,

**एक वर्ग ने उन्हें ‘नकारात्मक मानसिकता’ वाला कहा, तो दूसरे ने कहा कि “कम से कम कोई तो ज़मीन की बात कर रहा है।” लेकिन यह भी दिलचस्प है कि राहुल गांधी की पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेताओं शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने बयान दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है।**

क्षमता जोड़ रहा है। मगर जहां जीडीपी वृद्धि दर ऊंची है, वहीं कुछ बिंदु राहुल गांधी के बयान को जरूर प्रासंगिक बना सकते हैं जैसे बेरोजगारी की स्थिति। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर 7 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। युवाओं में बेरोजगारी की दर तो और भी अधिक है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। स्नातकों और शिक्षित युवाओं के लिए अवसरों की कमी एक गहरा संकट है। जीडीपी बढ़ती है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं बढ़ते – यह प्रश्न बेहद गंभीर है। इसी प्रकार भले ही सरकार कहे कि प्रमुख रोजगारी नियंत्रण में है, लेकिन आम जनता के लिए रसोई गैस, पेट्रोल, खाद्य वस्तुएं, दवाइयां और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों पर खर्च भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को सुहावने आर्थिक आंकड़े खोखले लगने लगते हैं और विपक्ष के नेता की अतिशयोक्ति वाली टिप्पणी बहुतां को भाने लगती है।

उधर ऑक्सफ़ाम की रिपोर्ट भारत में आर्थिक असमानता की बात करती है। वह कहती है कि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ प्रतिशत अमीरों के पास केंद्रित है। यदि आर्थिक विकास केवल कुछ लोगों को ही समृद्ध बनाए और बाक़ी देश हाशिये पर रहे, तो उसे ‘मृतप्रायः’ कहना बहुतां को अतिशयोक्ति नहीं लगता। अनेक अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में विकास हो रहा है, लेकिन वह असंतुलित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी एजेंसियां भारत को विकास दर को सराहते हुए भी बार-बार इस पर ज़ोर देती हैं कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश आवश्यक है ताकि देश की आबादी में आर्थिक असमानता कम हो सके।

यह जरूर है कि राहुल गांधी का “मरी हुई अर्थव्यवस्था” वाला बयान भापाई दृष्टि से अत्यंत आक्रामक है। इसमें अतिशयोक्ति अवश्य है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मरी हुई तो कतई नहीं है – वह गतिमान है, बढ़ रही है, और कुछ क्षेत्रों में तेजी से भी बढ़ रही है। लेकिन यह भी सच है कि देश की बड़ी आबादी उस विकास को महसूस नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी का बयान उसी भावना को उजागर करता है जिसे लाखों लोग रोज़ अनुभव करते हैं: नौकरी नहीं मिल रही, छोटा व्यापार नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ रही है। राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक रूप से भले ही उतेजक हो, लेकिन वे इस चीकाने वाली टिप्पणी से उस गहरी वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं जिसमें भारत में आर्थिक विकास और आम आदमी के अनुभव के बीच एक बड़ी खाई है। भारत की अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से जीवंत है, लेकिन जब वह करोड़ों लोगों को न्यूनतम गरिमा का भाव और अवसर नहीं दे पाए, तो उसके ‘जीवंत’ होने पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। सच्चाई शायद राहुल गांधी के शब्दों और सरकारी आंकड़ों के बीच कहीं है। भारत को केवल विकास नहीं, समावेशी और न्यायपूर्ण विकास की आवश्यकता है। जब तक आम जनता को आर्थिक सुरक्षा और अवसर नहीं मिलते, तब तक जीडीपी के आंकड़े सिर्फ कागजी विकास लगेगे – ज़मीनी सच्चाई नहीं। इसलिए यदि भारत को वास्तव में ‘विकासशील’ से ‘विकसित’ राष्ट्र बनाना है, तो उसे सिर्फ जीडीपी वृद्धि पर ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समावेशी विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ पूंजी निवेश और निजीकरण से समस्याएं नहीं सुलझेंगी। इसके लिए सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र में धकेलने की अंधी दौड़ से बचकर आना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुदृढ़ सार्वजनिक सेवाओं की गिरावट के दौर में सरकार को ऐसे उलाहने झेलने पड़ेंगे। देश की अर्थव्यवस्था आमजन को तभी जीवंत लग सकती है जब उनकी भी उसमें बाबरी की भागीदारी हो। इसके लिए सारी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को सुधराना होगा जो वर्तमान में आंकट घ्राणचार के दलदल में धंसी हुई है। कार्यपालिका लोकतंत्र का प्रमुख स्तम्भ है। वही लोकनीतियों का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। मगर विधायिका सिर्फ संसदीय सत्ता की प्रतिस्पर्धी राजनीति में सिमट कर रह गई है और सारे राजनेता एक-दूसरे को नीचा दिखाते और छिल्ली उड़ाने के खेल में लगे हैं। राजनेता भी प्रष्टाचार की कॉलिख से अछूते नहीं रहे हैं। राजनेताओं को देश की समस्याओं और गरीबी का कुछ भान भी है ऐसा लगता ही नहीं। अर्थव्यवस्था भले ही जीवंत और लचीली है और उसमें विकास की मजबूत संभावनाएं हैं मगर प्रशासनिक तंत्र तथा राजनीतिक व्यवस्थाएं लोगों को उसे महसूस नहीं होने देती। जब कोई राजनेता “मृत अर्थव्यवस्था” जैसा आरोप लगाता है, जो भले ही साक्ष्य समर्थित नहीं हो, तब भी वह झंझोड़ कर जगाने वाला जरूर होता है जिसे बहुत से लोग देश के लिए अपमानजनक मान लेते हैं।

–अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

# सरकारी स्कूल तभी सुधरेंगे, जब सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे



अशोक कुमार

एक ओर हम डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रख चुका है, वहीं हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। देश के हजारों जर्जर स्कूल के कारण बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है! हजारों स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं भवन जर्जर हैं तो कहीं बिजली, फनीचर और शौचालय की सुविधा नहीं है।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में हाल ही में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढहने से सात बच्चों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कौन जिम्मेदार है?

Unified District Information System for Education (UDISE) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में केवल 57.2% सरकारी स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध है और सिर्फ 53.9% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और शौचालय की

सुविधाएं हैं, लेकिन सिर्फ 52.3% स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था है। कम होता नामांकन और बढ़ता ड्रॉपआउट रेट।

सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2023-24 में, सरकारी स्कूलों में कुल छात्रों की संख्या में 3.7 लाख की कमी आई है। जहां देश की आबादी और गरीबी दोनों बढ़ रही हैं, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराने लगे हैं। योग्य और पर्याप्त शिक्षक नहीं।

सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन उनकी योग्यता और संख्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जो शिक्षक हैं उनमें से बड़ी संख्या में उनकी शैक्षणिक योग्यता मानकों पर खरी नहीं उतरती। परिणामस्वरूप, छात्रों की पढ़ाई और प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

**नई शिक्षा नीति 2020 के बावजूद गिरावट**

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। लेकिन, इसके बावजूद सरकारी स्कूलों के आंकड़े और गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाएं अधिकांश स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के नामांकन और ड्रॉपआउट दर में गिरावट ने नीति के उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

**क्या सरकारी शिक्षा विभाग सिर्फ एक एजेंसी बनकर रह जाएगा?**

अगर सरकारी स्कूलों की यह स्थिति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में शिक्षा विभाग केवल एक परीक्षा

आयोजित करने वाली और प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगा। सरकारी स्कूलों का मूल उद्देश्य – शिक्षा प्रदान करना – धीरे-धीरे समाप्त होता दिख रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 18 अगस्त 2015 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह फैसला शिव कुमार पाठक और कई अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान आया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और न्यायपालिका के सदस्य अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भेजें। यह आदेश उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता था “जो राज्य के खजाने या सार्वजनिक धन से कोई लाभ, सुविधा, वेतन आदि प्राप्त करते हैं”।

अदालत ने सरकारी स्कूलों की ‘उपनीय स्थिति’ पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसका कारण “प्रशासन की वास्तविक भागीदारी की कमी” बताया। फैसले का मुख्य तर्क यह था कि यदि अधिकारियों और राजनेताओं को अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे स्कूलों की आवश्यकताओं को गंभीरता से देखेंगे और उनकी अच्छी स्थिति सुनिश्चित करेंगे। इससे स्कूलों में जवाबदेही और निगरानी बढ़ेगी।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने यह भी टिप्पणी की कि यह कदम विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को एक-दूसरे के साथ बांधकर करने और घुलने-मिलने का अवसर देगा, जिससे “समाज

को जमीनी स्तर पर बदलने में क्रांति” आएगी और आम आदमी के बच्चों को आत्मविश्वास और अन्य अवसर मिलेंगे। अदालत ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में राजनीतिक कारणों से रिक्तियों को बनाए रखने और अक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का भी उल्लेख किया। यदि कोई बच्चा निजी स्कूल में भेजा जाता है, तो माता-पिता द्वारा उस बच्चे के लिए भुगतान की जा रही फीस के बराबर राशि उनके मासिक वेतन से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को “वेतन वृद्धि, पदोन्नति के अवसर जैसे अन्य लाभों से भी वंचित किया जा सकता है”। एकत्रित राशि का उपयोग सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए किया जाना था।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए अनिवार्य करने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2015 का फैसला प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ।

यह फैसला, हालांकि लागू नहीं हुआ, सार्वजनिक शिक्षा की बिगड़ती स्थिति और अधिकारियों के ‘पाखंड’ इसके खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक बयान के रूप में कार्य करता है। इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करना जरूरी है! इससे मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, लोक सेवकों की जवाबदेही और शैक्षिक असमानता के बारे में एक तीखी बहस छेड़नी चाहिए। इस विशिष्ट

जनादेश के गैर-कार्यान्वयन ने सरकार को सार्वजनिक शिक्षा में सुधार के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का पता लगाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की रिक्रिटिंग और शिक्षण की गुणवत्ता के अंतर्निहित मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, यह दर्शाता है कि जिन मुख्य समस्याओं को फैसले ने संबोधित करने की कोशिश की थी, वे इस विशिष्ट तंत्र के माध्यम से काफी हद तक अनसुलझी रही हैं।

2015 के फैसले को एक “ऐतिहासिक फैसला” के रूप में सराहा गया था, जिसका इरादा ‘सही’ था, फिर भी इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। यह “अप्रवर्तित ऐतिहासिक” फैसलों की एक श्रेणी बनाता है – वे जो अपने कानूनी घोषणाओं और सामाजिक इरादों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कार्यान्वयन अंतराल के कारण ठोस परिवर्तन में विफल रहते हैं। यह न्यायिक घोषणाओं और वास्तविक शासन के बीच के अंतर को उजागर करता है। एक अदालत एक साहसिक आदेश जारी कर सकती है, लेकिन इसका वास्तविक दुनिया का प्रभाव राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करता है। यह भी सुझाव देता है कि कुछ न्यायिक हस्तक्षेप, हालांकि कागजी पर शक्तिशाली होते हैं, जटिल सामाजिक-राजनीतिक वातावरण में बहुत महत्वाकांक्षी या लागू करने में मुश्किल हो सकते हैं।

–अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभाग अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

# उत्तर-पश्चिम रेलवे ने अस्तित्व में आने के बाद भारतीय रेलवे में अलग पहचान बनाई

**अपनी स्थापना से 22 वर्षों के सफर में उत्तर-पश्चिम रेलवे आज देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, औद्योगिक विकास में भागीदार बनकर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है**



वेदप्रकाश

उत्तर-पश्चिम रेलवे 1 अक्टूबर, 2002 को अस्तित्व में आने के बाद आज भारतीय रेलवे में अलग पहचान बना चुका है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के चारों मण्डल जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर पर्यटन, औद्योगिक, सामरिक एवं सामाजिक रूप से विशेष महत्व रखते हैं। अपनी स्थापना से 22 वर्षों के सफर में उत्तर-पश्चिम रेलवे आज देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास में भागीदार बन कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

उत्तर-पश्चिम रेलवे का क्षेत्राधिकार राजस्थान के प्रमुख पर्यटकों स्थलों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। रेलवे द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विरासत के साथ-साथ विकास को आधार बना कर कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे पर्यटन स्थलों तक पहुँच के मामले में सबसे सुविधाजनक, रोमांचकारी और सुरक्षित साधन होने के साथ ही स्वयं भी पर्यटन का केन्द्र है। उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा हैरिटेज संरक्षित करने और इसको आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष पहल की जा रही है जिससे आमजन का केंद्र बन गया है और इसे अजमेर का नया दूरिस्ट पॉइंट भी कहा जा सकता है। रेल म्यूजियम में अजमेर मंडल सहित भारतीय रेल की महान ऐतिहासिक व समृद्धिविरासत से परिचय कराया गया है। रेल संग्रहालय परिसर में आकर्षण

मीटर गेज ही रखा गया है। इस खण्ड पर मारावड़ खामली घाट-मारावड़ के बीच प्रदेश की पहली हैरिटेज ट्रेन वैली क्वीन संचालित की जा रही है।

इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05 अक्टूबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर किया गया। वैली क्वीन हैरिटेज ट्रेन में एक वातानुकूलित चेयर कार एवं एक पॉवर कार कोच के साथ एक डीजल इंजन को भाप इंजन जैसा बनाया गया है। यात्रा में यात्रियों को हरी-भरी चाटियां, पेहाड़ियां, उलूभ वनस्थितियों और स्थानीय जीव जन्तुओं के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। इस मार्ग में लगभग 100 साल पुरानी दो सुर्रंगें और जलघराओं पर 172 पुल हैं।

ट्रेन के कोच में एनाउंसमेंट के साथ टोनी स्क्वीन भी लगाई गई है जिसमें पूरे मार्ग एवं गोरामघाट की वादियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी दी जाती है। पूरे दिन की यात्रा में यात्रियों को प्राकृ तिक सौंदर्य एवं रोमांच का अनुभव प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त अजमेर मंडल की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने व आमजन को भारतीय रेल की समृद्ध विरासत से परिचित करवाने के लिये अजमेर में रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया है। अजमेर मंडल की ऐतिहासिक विरासत को और संरक्षित करने व आमजन को भारतीय रेल की समृद्ध विरासत से रूबरू करवाने के लिए अजमेर में नसीरबाद रोड पर रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो लगभग 16000 वर्ग मीटर परिसर में फैला है।

नसीरबाद रोड, मार्टिण्डल ब्रिज समीप स्थित यह रेल संग्रहालय स्थानीय और अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और इसे अजमेर का नया दूरिस्ट पॉइंट भी कहा जा सकता है। रेल म्यूजियम में अजमेर मंडल सहित भारतीय रेल की महान ऐतिहासिक व समृद्धिविरासत से परिचय कराया गया है। रेल संग्रहालय परिसर में आकर्षण

का केंद्र एक टॉय ट्रेन है जिसके लिए मीटर गेज का ट्रैक बिछाया गया है। इस टॉय ट्रेन को मीटर गेज की 5 पुरा टूर्णलियों से बनाया गया है। रेल म्यूजियम में 3 डी प्रभावों के साथ कैनवास पर बनाई गई सिनोग्राफी, साइनेज, सबसे पुराने भाप इंजन का मॉडल, राजस्थान के तीर्थ स्थानों के मार्ग, ‘रेलवे की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग’ आदि पर आधारित इंटरैक्टिव मॉडल सहित अन्य ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं प्रदर्शित की गयी हैं।

पैलेस ऑन व्हील्स भारत की पहली लक्जरी पर्यटक ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह ट्रेन दिल्ली से प्रारम्भ होकर जयपुर, रायथम्बोर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर होते हुए आगरा पहुंचती है।

प्रत्येक कोच का नाम पूर्व रियासतों के नाम पर अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, इंदौरगढ़, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, सिराही और उदयपुर रखा गया है। ट्रेन में महाराजा और महारानी दो रेस्तरां बनाए गए हैं, जिनमें स्वादिष्ट राजस्थानी और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसे जाते हैं।

अब बात करें रेल से दिखने वाली विश्व प्रसिद्ध सांभर झील को। राजस्थान में जयपुर के समीप स्थित सांभर में लवण जल (खारे पानी) की झील है। यह झील समुद्र तल से 1,200 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें चार नदियाँ (रुपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेल) आकर गिरती हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है।

यह झील उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर एवं जोधपुर मण्डल को जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्ग जयपुर-फुलेरा-मेडता-जोधपुर के अंगरंग आती है।

रेलवे लाइन इस झील को लगभग 2 भागों में बांटती है। इस झील के मध्य से गुजरती रेल लाइन से मनमोहक नजारा दिखता है एवं यह पर्यटकों के मध्य खासा लोकप्रिय रेलमार्ग है।

भारतीय रेलवे वोल्क फॉर लोकल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण “एक स्टेशन-एक उत्पाद” योजना स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए बिक्री आउटलेट प्रदान करती है। स्थानीय कलाकारों, उद्यमियों, बुनकरों एवं छोटे व्यवसायों को मंच प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर “एक स्टेशन-एक उत्पाद” योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना से स्थानीय लोक कला के कारीगरों को लाभ तो मिल ही रहा है साथ ही रेल यात्रियों को स्टेशन पर ही स्थानीय उत्पाद मिल रहे हैं। इस योजना में वर्तमान में उत्तर-पश्चिम रेलवे पर जयपुर में सांगानेरी प्लिंट के कपड़े, अजमेर में गुलाब से बने उत्पाद, उदयपुर में हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलोने, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट आइटम खासे लोकप्रिय हो रहे हैं।

उत्तर-पश्चिम रेलवे पर 77 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास में स्थानीय कला के अनुरूप हैरिटेज को ध्यान में रखकर आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को उच्चस्तरिय सुविधाएं उपलब्ध होगी और उनकी सुखद अनुभूति मिलेगी। स्टेशनों के पुनर्विकास की परिकल्पना में इस विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है कि इसे सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे यह कला के साथ-साथ शहर के निवासियों के भी आकर्षण का केन्द्र बने।

अजमेर में स्थापित रेल कारखाना 1876 में प्रारम्भ किया गया था, यह भारत के प्रमुख कारखानों में से एक है। यह मीटरगेज डीजल लोको का सबसे बड़ा केंद्रिज

और वैगन कारखाना था। वर्तमान में ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक के प्रमुख मदे कोच, वैगन, डीईएमयू, रेल बस आदि का अनुत्क्षण कर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस कारखाना की बिल्डिंग हैरिटेज को दर्शाती है और यह प्रदर्शित करती है कि वह लम्बे समय से मजबूती के साथ रेलवे के रोलिंग स्टॉक के अनुत्क्षण में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

गडरा रोड, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण गांव है, जो ऐतिहासिक, सांत्तिक और सामरिक दृष्टि से विशेष पहचान रखता है। यह गांव पाकिस्तानी की सीमा से सटा हुआ है और भारतीय रेलवे के पश्चिमी छोर पर स्थित है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने बाड़मेर जिले में भारतीय रेलवे ट्रैक पर बमबारी की थी, जिसके माध्यम से सेना को रसद पहुंच रही थी। इस बमबारी से रेलवे ट्रैक को बहुत क्षित हुई और सेना को रसद की आपूर्ति बंद हो गई।

इस स्थिति में रेलकर्मियों ने अपने जान का परवाह न करते हुए रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए बमबारी के बावजूद रेल ट्रैक का ठीक कर रेल संचालन को प्रारम्भ किया। भारत का पहला रेलवे शहीद स्मारक 1965 में भारत-पाक युद्ध में जान गंवाने वाले 17 रेल कर्मचारियों को समर्पित बाड़मेर जिले के गडरा रोड स्टेशन पर स्थापित किया गया है। राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया।

रेलवे पर्यटन और स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें नवाचारों को सम्मिलित कर नई संभावनाओं पर भी निरंतर कार्य कर रहा है। रेलवे उन क्षेत्रों की भी पहचान कर रहा है जहाँ हैरिटेज संरक्षण किया जा सके और आमजन को उस गौरवशाली अतीत से रूबरू करवाया जा सके।

वेदप्रकाश, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेलवे।



पंडित अनिल शर्मा

शुरू-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज यमघट योग सूर्योदय से दिन 1:00 तक है। राजयोग दिन 1:00 से 2:09 तक है। आज प्रदीप व्रत, पवित्र बारस, विष्णु पवित्रा रोपण, दामोदर द्वासी, वैधुति पुण्य है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:15 तक, शुभ 10:54 से 12:33 तक, चर 3:50 से 5:29 तक, लाभ 5:29 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08

## राशिफल

**बुधवार 6 अगस्त, 2025**

सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2082, मूल नक्षत्र दिन 1:00 तक, वैधुति योग प्रातः 7:17 तक, बरलव करण दिन 2:09 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन,

शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज यमघट योग सूर्योदय से दिन 1:00 तक है। राजयोग दिन 1:00 से 2:09 तक है। आज प्रदीप व्रत, पवित्र बारस, विष्णु पवित्रा रोपण, दामोदर द्वासी, वैधुति पुण्य है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:15 तक, शुभ 10:54 से 12:33 तक, चर 3:50 से 5:29 तक, लाभ 5:29 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08



### मेष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।













# ट्रंप ने दवाओं पर 2 5 0 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी

वर्ष 2020 में भारत ने 6500 करोड़ रुपये की दवायें अमेरिका भेजी थीं

नई दिल्ली, 05 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर ढाई सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दरअसल, सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फार्मास्यूटिकल्स पर शुरू में छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर डेढ़ सौ प्रतिशत और उसके बाद ढाई सौ प्रतिशत तक कर देंगे। उन्होंने यह टैरिफ एक से डेढ़ साल में बढ़ाने की बात कही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दवाइयां अमेरिका में ही बनाई जाएं। उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा विदेशी

■ **ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिये भारत व चीन पर निर्भर नहीं रहे। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली दवायें वहीं बनाई जायें।**

देशों पर निर्भर न रहे, खासकर भारत और चीन पर। इस समय अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए भारत पर काफी निर्भर है। डॉनल्ड ट्रंप के इस ऐलान से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है।

भारत और अमेरिका के बीच फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बड़ी डील होती है। दरअसल, भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका को दवाइयां सप्लाई करता है, जिनमें जेनेरिक दवाइयां, वैक्सिन और

एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। 2020 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत ने अमेरिका को लगभग 7.5 अरब डॉलर यानी करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां भेजी हैं। वहीं, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, अमेरिका में जो जेनेरिक दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा भारत से ही इंपोर्ट की जाती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद

भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर ट्रंप भारत की दवाओं पर ढाई सौ प्रतिशत तक टैरिफ लगाते हैं, तो कंपनियों को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को दोगुना करना पड़ेगा। कीमतें बढ़ जाने से अमेरिका के लोग इन दवाओं को खरीदना कम कर देंगे, जिससे कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि अब भारतीय कंपनियां अमेरिका में मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने पर भी जोर दे सकती हैं। भारत जेनेरिक दवाएं सबसे सस्ती और उतनी ही असरदार होती हैं। अमेरिका में ज्यादातर डॉक्टर इन्हीं दवाओं को लिखते हैं।

## बार-बार ब्याज दर घटाने ....

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) राजकोषीय नीति भी गिरते कर राजस्व और सीमित बजटीय गुंजाइश के कारण बंधी हुई है, जिससे पूरा बोझ मौद्रिक उपायों पर आ गया है।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि “ब्याज दरों में कटीती कोई जादू की छड़ी नहीं है।” उन्होंने जोर देकर कहा था कि किसी भी ठोस आर्थिक पुनरुद्धार के लिए आधारभूत सुधार, जैसे अवसंरचना और कौशल विकास आवश्यक हैं। के ज्योति प्रकाश गाडिया और कोटक महिंद्रा की उपासना भारद्वाज दोनों ने कम से कम 50 आधार अंकों की और कटीती की वकालत की है, यह कहते हुए कि मौद्रिक नीति में अभी भी संभावनाएं हैं—अगर इसे संरचनात्मक और राजकोषीय समर्थन के साथ मिलाया जाए।

एसबीआई के सौम्य कांती घोष और पौरामल के देवोपम चौधरी पहले ही जून में हुई 50 बीपीएस कटीती का सटीक अनुमान लगा चुके थे और अब

उनका अनुमान है कि अगर महंगाई नियंत्रण में रही, तो रेपो दर 2026 की शुरुआत तक 5 प्रतिशत के करीब आ सकती है। फिर भी, भारत रेटिंग्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में ऋण वृद्धि धीरे-धीरे ही बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में स्वीकार किया कि भले ही केन्द्रीय बैंक ने “महंगाई के खिलाफ लड़ाई जीत ली हो”, लेकिन “असली युद्ध अभी बाकी है।” उन्होंने यह भी बताया कि आरबीआई का रुख अब तटस्थ है, जिसका अर्थ है कि आगे की नीतियां महंगाई और विकास के रुझानों पर निर्भर करेंगी, सिर्फ वर्तमान आंकड़ों पर नहीं। मूल बात यह है कि मौद्रिक नीति ने अपना काम कर दिया है, लेकिन भारत की आर्थिक बहाली केवल ब्याज दरों में कटीती से संभव नहीं है। जब तक उपभोक्ता विश्वास नहीं लौटता, व्यापक सुधार नहीं होते, और राजकोषीय समर्थन नहीं मिलता, आरबीआई के कदम ऐसे ही रहेंगे, जैसे ईंधन तो है, पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा।

### पूर्व राज्यपाल सत्यपाल ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) केजरीवाल ने मलिक के निधन पर शोक व्यक्त करते हुये, उन्हें एक बेबाक, निडर, ईमानदार और सत्ता को आईना दिखाने वाला साहसी व्यक्ति बताया। जिन्दगी भर किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले सत्यपाल मलिक का जीवन एक साधारण परिवार के लड़के से देश के पांच राज्यों के राज्यपाल पद तक पहुंचने की कहानी है।

### कावड़ यात्रा में ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

धाम में भगदड़ मच गई। घबराहट और अत्यधिक भीड़ के चलते दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि दो महिलाओं की हालत गंभीर है। वहीं 8 से 10 लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें भी जिला अस्पताल पहुंचाया गया है।

### खड़गे-राहुल-प्रियंका...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

और चिंताजनक है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करें। बाड़ा ने कहा उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना में कुछ लोगों की मृत्यु और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने का समाचार सुनकर मन को अत्यंत दुःख पहुंचा। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, “मैं वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। मैं ईश्वर से सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूं।” केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में हुई बादल फटने की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस विनाशकारी आपदा में हुये जान-माल के नुकसान पर संवेदना प्रकट की और प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने एनडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियों को तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं।

लगातार मजबूत हो रही है। कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता भी उन्हें पार्टी का भविष्य मानते हैं। हालांकि ममता अभी तक उन्हें नेतृत्व सौंपने को तैयार नहीं दिखतीं—शायद पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए। लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति और टिकट वितरण में अभिषेक की अहम भूमिका रहेगी। फिलहाल 70 साल की ममता बनर्जी अपनी “चप्पल” टांगने के मूड में नहीं है।

## रूस ने ट्रंप की भारत को ...

स्पष्टता आने की उम्मीद है कि भारत रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति को कैसे आगे बढ़ाएगा, खासकर जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मास्को भारत को और सस्ती दरों पर तेल दे सकता है।

दिसंबर 2022 से रूस के कच्चे तेल की अधिकतम कीमत पर प्रति बैरल 60 अमेरिकी डॉलर निर्धारित है, जिसे जी7 देशों ने तय किया था। हालांकि, इस मूल्य सीमा की आलोचना भी हुई, क्योंकि यह अपेक्षित लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक अप्रभावी रही।

ट्रंप ने सोमवार को दुथ सोशल पर की गई एक पोस्ट में भारत पर आरोप लगाया कि वह रूस से तेल खरीदकर लाभ कमा रहा है, जबकि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। भारत न केवल बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि तेल खरीदने के बाद, उस तेल को बड़ी मात्रा को खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग रशियन वॉर मशीन द्वारा मारे जा रहे हैं। इसी कारण, मैं भारत पर अमेरिका को दिए जाने वाले शुल्क में भारी वृद्धि करूंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!!!

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार से वे रूस और उसके ऊर्जा निर्यात खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध

## भारत को धमकाने वाले...

■ **लेकिन भारत के मामले में ट्रंप जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत इतना ताकतवर नहीं है कि उन्हें जवाब दे सके। हालांकि, भारत ने प्रतिरोध जताया, पर, चीन की तुलना में भारत की प्रतिक्रिया बेहद संयमित मानी जा रही है।**

में अपनी जिम्मेदारियों से साफ तौर पर किनारा कर लिया। परमाणु हथियारों और उनकी तैनाती को लेकर आक्रामक होती बातचीत के बीच रूस को यह कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक तरह

का आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। ट्रंप ने भारत पर रूस को युद्ध में मदद देने का आरोप लगाते हुए भारतीय निर्यात पर बहुत ऊंचा शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अब रूस की तरह एक “मरी हुई अर्थव्यवस्था” है।

### ‘भारत पर 24 घंटे में ....

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

वह एक तरह सेयुद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। हम 25 प्रतिशत पर सहमत हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूंगा।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह भारत से आयात पर लगने वाले टैरिफ को अगले 24 घंटों में मौजूदा 25 प्रतिशत की दर से ”काफी” बढ़ा देंगे,

क्योंकि भारत लगातार रूसी तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ”वे युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं, और अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं, तो मुझे खुशी नहीं होगी।” उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ मुख्य समस्या यह है कि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने भारत के लिए कोई नई टैरिफ दर नहीं बताई।

**MARUTI SUZUKI**

**NEXA**

# THE GRAND VITARA S-CNG

## DRIVEN BY TECH

**S-CNG**

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



**STARTING PRICE**  
₹ 13 48 000\*

**SUPERIOR MILEAGE**  
26.6 km/l<sup>#</sup>

**GRAND VITARA**



FACTORY-FITTED S - CNG



CRUISE CONTROL



SMARTPLAY PRO+



PAINTED ALLOY WHEELS



6 AIRBAGS

**3 years** 100 000 km  
**WARRANTY\***  
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

**BENEFITS UP TO**  
₹ 49 100\*

SCRAPPAGE BONUS AVAILABLE  
AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.

**FASTEST**  
**3 LAKH**  
**SALES**  
IN THE SEGMENT



SCAN TO CONNECT TO  
A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @  
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

**UDAIPUR: NEXA GOVERDHAN VILAS** (TECHNOY MOTORS PH: 8306300695), **NEXA CENTRAL UDAIPUR** (NAVNEET MOTORS PH: 7665016580), **BANSWARA: NEXA BANSWARA CENTRAL** (NAVNEET MOTORS PH: 9376240719), **SIROHI: NEXA CENTRAL SIROHI** (NAVNEET MOTORS PH:7665016625) **RAJSAMAND: NEXA RAJNAGAR** (TECHNOY MOTORS PH: 9251988300)

For detailed T&C kindly visit your nearest dealership. Creative visualisation. For details on functioning of safety features, including airbags, kindly refer to the owner's manual. \*All offers are brought to you by NEXA dealers only. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. Offers may vary subject to the model and variant purchased and shall be applicable till stocks last. For more details regarding offers please contact your nearest NEXA dealership. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. \*3 years or 100 000 km whichever is earlier.

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वैआई मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूगी नाका के पास, अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौरा फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

